SUN LAUNCHES NEW DISTRIBUTION COMPANY

Sun TV Network has launched a new company - TVCH Distribution Services Private Limited. The new company will handle distribution for Sun TV Network in Kerala for Multi System Operators (MSOs) and DTH operators.

The MSO distribution mandate into various subsidiaries namely Gemini Distribution Services Private Limited (GDSPL), Kal Media Services Private Limited (KMSPL), and Sun Distribution Services Private Limited (SDSPL).

TVCH

Distrubution Services Pvt Ltd

GDSPL since the advent of the New Tariff Order has been the Single Point of Contact (SPOC) for Multi System Operators (MSOs) based out of Andhra Pradesh and Telangana looking for signals while SDSPL has been the SPOC for MSOs based out of Karnataka, and Rest of India (North, East, and West).

KMSPL which currently is the SPOC for MSOs based out of Kerala and Tamil Nadu & Pondicherry will soon only handle the mandate for Kerala with the newly setup TVCH set to become the SPOC for MSOs based out of Tamil Nadu & Pondicherry.

TVCH has also been named as the designated company for receiving requests for interconnection from DTH operators on behalf of SUN. The designated person for handling DTH operators remains the same as earlier even though TVCH will now be the authorised agent on behalf of SUN.

REPUBLIC TO LAUNCH ACROSS INDIA

Republic has drawn up an ambitious plan to launch across various states and also go global. Arnab Goswami has announced that Republic Media Network will launch news channels in every regional language in the next one year.

"We will also take Republic Media Network globally in the next 16-17 months," Goswami added.

IN10 MEDIA LAUNCHES KIDS' CHANNEL

In10 Media Network ventured into the kids' entertainment space on Children's Day with the launch of

नयी वितरण कंपनी लॉन्च की सन ने

सन टीवी नेटवर्क ने टीवीसीएच डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक नयी कंपनी लॉन्च की है। नयी कंपनी केरल में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) व डीटीएच ऑपरेटरों के लिए सन टीवी नेटवर्क के वितरण का काम संभालेगी।

एमएसओ वितरण विभिन्न सहायक कंपनियों जैसे जेमिनी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीडीएसपीएल), काल मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (केएमएसपीएल) और सन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एसडीएसपीएल) के नाम से किया जायेगा।

नये टैरिफ आदेश आने के बाद से जीडीएसपीएल आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बाहर स्थित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए सिंगल प्वाइंट ऑफ कन्टैक्ट (एसपीओसी) रहा है, जो सिगनल की तलाश में हैं, जबकि एसडीएसपीएल कर्नाटक और शेष भारत (उत्तर, पूर्व और पश्चिम) के बाहर एमएसओ के लिए एसपीओसी रहा है।

केएमएसपीएल जो कि वर्तमान में केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी से बाहर स्थित एमएसओ के लिए एसपीओसी है, जल्दी ही केवल केरल के लिए अपनी जिम्मेवारियों को संभालेगा, जिसमें नया सेटअप टीवीसीएच होगा, जो तमिलनाडु व पांडिचेरी से बाहर एमएसओ के लिए एसपीओसी बनने के लिए निर्धारित है।

सन की ओर से डीटीएच ऑपरेटरों से इंटरकनेक्शन के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए टीवीसीएच को नामित कंपनी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। डीटीएच ऑपरेटरो को संभालने के लिए नामित व्यक्ति पहले की तरह ही बना रहेगा, हालांकि टीवीसीएच अब सन की ओर से अधिकृत एजेंट होगा।

पूरे भारत में लॉन्च होगा रिपब्लिक

रिपब्लिक ने विभिन्न राज्यों में लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी योजना बनायी है और साथ ही यह वैश्विकस्तर पर भी जाने की तैयारी कर रहा है। अर्नब गोस्वामी ने घोषणा की है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अगले एक साल में क्षेत्रीय भाषा में समाचार चैनल लॉन्च करेगा।

श्री गोस्वामी ने कहा कि 'हम अगले 16-17 महीनों में विश्वस्तर पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ले जायेंगे।'

किड्स चैनल लॉन्च किया इन10 मीडिया ने

इन10 मीडिया नेटवर्क ने नये प्रीमियम चैनल गुब्बारे-मस्ती की फुवारे' के लॉन्च के साथ बाल दिवस को बच्चों के मनोरंजन क्षेत्र में कदम

new premium Hindi channel, Gubbare — Masti Ke Phuwarre.The network runs channels such as Epic TV – India Ka Apna Infotainment, ShowBox – Apna Music, Apna Swag and Filamchi – Filman Ka Laalchi.

Aditya Pittie, Managing Director, In10 Media Network, said, "At In10 Media Network, we are focused on building scalable businesses and strategically expanding our footprint in the industry. In our country, television continues to be a primary viewing platform for kids' entertainment among most households. We are excited to launch Gubbare on Children's Day and build an affinity with kids through the channel's distinctive and exciting programming."

Gubbare, a pay channel, will be a part of the 'Apna Epic Value Pack'. It would be available on all major DTH and cable operators across India.

ADITYA PITTIE

रखा। यह नेटवर्क एपिक टीवी–इंडिया का अपना इंफोटेनमेंट, शो बॉक्स–अपना म्यूजिक, अपना स्वैग और फिल्मची–फिल्मान का लालची जैसे चैनल चलाता है।

इन10 मीडिया नेटवर्क के प्रबंध निदेशक आदित्य पिट्टी ने बताया कि 'इन10 मीडिया नेटवर्क में हम स्केलेबल व्यवसायों के निर्माण और रणनीतिक रूप से उद्योग में अपने पदचिन्ह का विस्तार करने पर केंद्रित है। हमारे देश में, अधिकांश घरों में बच्चों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन एक प्राथमिक देखने का प्लेटफॉर्म बन हुआ है। हम बाल दिवस पर गुब्बारे को लॉन्च करने और चैनल के विशिष्ट और रोमांचक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के साथ संबंध बनाने के लिए उत्साहित हैं।'

गुब्बारे एक पे चैनल है जो कि 'अपना एपिक वैल्यू पैक' का हिस्सा होगा। यह पूरे भारत में सभी प्रमुख डीटीएच और केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

CENTRE MOOTS FREE SPEECH

Supreme Court has urged the Govt to exercise its powers under the Cable TV Networks (Regulation) Act against TV channels to have an effective oversight on the contents of TV programmes. The Govt on the other hand argued that it respected the media's right to free speech and was not keen to play the regulator.

A bench of CJI SA Bobde and justices AS Bopanna and V Ramasubramanian expressed displeasure over the Centre's response to Jamiat Ulama-i-Hind's petition alleging the government did precious little to stop the media from targeting Muslims during the Covid-19 pandemic by making hateful reports on the Tablighi Jamaat congregation in Nizamuddin. In its affidavit, the Centre had said that by and large, most mainstream newspapers and web portals reported responsibly on the event. It said during the initial period of the pandemic, when some Tablighi Jamaat members were found Covid positive, it received media and public attention. It also detailed the number of accounts and URLs that were blocked to stop circulation of fake news targeting the minority community.

As the hearing progressed, its scope expanded to cover whether the government should use the powers it enjoys to regulate content on TV channels. The CJI told solicitor general Tushar Mehta, "We are not satisfied with

बोलने की आजादी पर केंद का जोर

सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी चैनलों के खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) एक्ट के तहत सरकार को टीवी कार्यक्रमों की सामग्री पर एक प्रभावी निगरानी रखने का आग्रह किया है। दूसरी ओर सरकार ने तर्क दिया है कि वह बोलने की आजादी के मीडिया के अधिकार का सम्मान करती है और नियामक की भूमिका के लिए उत्सुक नहीं है।

सीजेआई एसए बोबडे व जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने जमीयत उलम ए हिंद की याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई और सरकार ने निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात मंडली पर घृणास्पद रिपोर्ट बनाकर मीडिया को कोविद–19 महामारी के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने से रोकने के लिए बहुत कम काम किया। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि बड़े व मुख्यधारा के समाचार पत्रों और वेब पोटर्लो ने इस घटना पर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग नहीं की। इसने कहा कि महामारी की शुरूआती अवधि के दौरान, जब कुछ तब्लीगी जमात के सदस्यों को कोविद पॉजिटिव पाया गया, तब इसने मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित किया। इसमे अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित करने वाले फर्जी समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए अकाउंट व यूआरएल की भी विस्तृत जानकारी दी।

जैसे–जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, इसके दायरे का भी विस्तार होता गया कि क्या सरकार को टीवी चैनलों पर सामग्री विनियमित करने के लिए शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। सीजेआई ने महाधिवक्ता तुषार

the Centre's affidavit. We had asked what steps were taken by the government under the Cable TV Networks (Regulation) Act against fake news circulated by TV channels. What is the grievance redressal mechanism under the law? On both these points, your affidavit is silent despite us asking for it."

CODE FOR NEWS CHANNELS

Govt is looking to strengthen the regulatory mechanism for news media besides considering a new code of conduct for TV news channels.

PRAKASH JAVADEKAR

"Freedom of press is being discussed again today and I said that the way press freedom is being attacked, that is not good… Press Council of India (PCI) is another mechanism of self-regulation. Though the head is appointed by the government, it has representatives of press owners, editors, journalists, photographers and parliamentarians. But people are demanding that the PCI should be given more powers. That is also being considered," I&B Minister noted.

Noting the absence of a Press Council-like body to regulate TV news even though he referred to the National Broadcasting Standards Authority as an institution where "anyone can complain to them and they even punish the erring channels", Javadekar said, "But there are many channels that are not even members of that… and they have no restrictions… Such a system cannot exist..."

COMPLIANCE POLICY OF FDI

The Govt has notified compliance of policy on FDI in digital media.

All eligible entities involved in uploading and streaming of news and current affairs through digital media, to comply with the decision of Government, which had permitted 26 per cent FDI under Government approval route. The entities having foreign investment below 26 per cent may furnish intimation to the Ministry of Information and Broadcasting.

They have to provide details of the company, entity and its shareholding pattern along with the names and addresses of its Directors and shareholders.

The names and address of Promoters and Significant

मेहता से कहा, 'हम केंद्र के हलफनामें से संतुष्ट नहीं हैं। हमने पूछा था कि केवल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत सरकार ने टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित नकली खबरों के खिलाफ क्या कदम उठाये हैं। कानून के तहत शिकायत निवारण तंत्र क्या है?इन दोनों विंदुओं पर, आपका हलफनामा हमारे द्वारा मांगने के बावजूद चुप है।'

समाचार चैनलों के लिए कोड

सरकार, टीवी समाचार चैनलों के लिए एक नयी आचार संहिता पर विचार करने के अलावा समाचार मीडिया के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करना चाह रही है।

आईएंडबी मंत्रालय ने बताया कि 'प्रेस की आजादी पर आज फिर से चर्चा हो रही है और मैंने कहा कि जिस तरह से प्रेस की आजादी पर हमला किया जा रहा है वह अच्छा नहीं है…प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) आत्म नियमन का एक और तंत्र है। हालांकि इसके प्रमुख की नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें प्रेस मालिकों संपादकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों और सांसदों के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि पीसीआई को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। इस पर भी विचार किया जा रहा है। आईएंडबी मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि टीवी प्रसारण को विनियमित करने के लिए एक प्रेस काउंसिल जैसी संस्था की अनुपस्थिति को देखते हुए भले ही उन्होंने राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण को एक ऐसी संस्था के रूप में संदर्भित किया है, जहां 'कोई भी शिकायत कर सकता है और वे गलत चैनलों को दंडित कर सकते हैं, लेकिन कई चैनल हैं जो उसके सदस्य नहीं हैं…और उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है…इस तरह की प्रणाली मौजूद नहीं हो सकती।'

एफडीआई की अनुपालन नीति

सरकार ने डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति के अनुपालन को अधिसूचित किया है।

सरकार के निर्णय के अनुपालन के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार व करेंट अफेयर्स को अपलोड करने और स्ट्रीमिंग करने में शामिल सभी पात्र संस्थायें, जिन्होंने सरकार के अनुमोदन रूट के माध्यम से **26** प्रतिशत एफडीआई की अनुमोदन प्राप्त हुई थी। **26** प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली संस्थायें भी सूचना व प्रसारण मंत्रालय को सूचना दे सकती हैं।

उन्हें अपने निदेशकों व शेयरधारकों के नाम व पते के साथ कंपनी, इकाई व इसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न का भी विवरण प्रदान करना होगा।

Beneficial Owners, Permanent Account Number and the latest audited or unaudited Profit and Loss Statement and Balance Sheet along with the Auditor report.

The Ministry said, entities which, at present, have an equity structure with foreign investment exceeding 26 per cent will give similar details to the Ministry of Information and Broadcasting.

It said, any entity which intends to bring fresh foreign investment in the country has to seek prior approval of the Central Government, through the Foreign Investment Facilitation Portal of DPIIT.

GOVT ALLOWS INFRA SHARING

The Govt has allowed platform infrastructure sharing voluntarily for distribution of TV channels provided signals of HITS platform are distributed to subscribers via the cable operator.

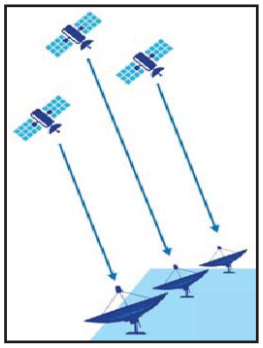

Govt has amended the Headend-in-the-Sky (HITS) guidelines by allowing sharing of infrastructure by HITS operators with multi-system operators (MSOs). The sharing of infrastructure between HITS and cable TV companies has been a long-pending demand of the distribution sector.

As per the new clauses added to the HITS guidelines, a HITS operator may share the platform infrastructure on a voluntary basis, in flexible ways, for distribution of TV channels provided that the signals of the HITS platform are distributed to subscribers through cable operator only and the encryption of signals, addressability and liabilities are not compromised.

The amended guidelines also allow sharing of transport stream transmitted by HITS platforms, between HITS operators and MSOs. Further, the HITS platform will not be allowed to be used as a teleport for the uplinking of TV channels.

An HITS operator willing to share its transport stream with an MSO should ensure that the MSO has a valid written interconnection agreement with the concerned broadcasters for distribution of Pay TV channels to the subscribers.

For an HITS operator to share infrastructure with an MSO, the operator will be allowed sharing only on Indian controlled satellites. A written permission from the Department of Space (DOS) will be required in this regard.

ZAKKA JACOB PROMOTED

CNN-News18, a leading English News channel has

प्रर्वतकों व प्रमुख लाभार्थियों के नाम व पते के अलावा स्थायी खाता संख्या व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ नवीनतम लेखा परीक्षित या अघोषित लाभ व हानि और बैलेंस शीट का विवरण देना होगा।

मंत्रालय ने कहा, मौजूदा समय में, विदेशी निवेश के साथ इक्विटी संरचना **26** प्रतिशत से अधिक है, आज से एक महीने के भीतर सूचना व प्रसारण मंत्रालय को समान विवरण देना होगा।

इसमें कहा गया है कि जो भी संस्थायें देश में नये विदेशी निवेश लाने का इरादा रखती है, उसे डीपीआईआईटी के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने इंफ्रा शेयरिंग की अनुमति दी

सरकार ने टीवी चैनलों के वितरण के लिए स्वेच्छा से प्लेटफार्म इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति दे दी है, बशर्ते केबल ऑपरेटर के माध्यम से ग्राहकों को हिट्स प्लेटफार्म के माध्यम से सिगनल वितरित किये जाते हैं। सरकार ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के साथ हिट्स ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढ़ांचे के साझाकरण की अनुमति देकर हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। हिट्स व केबल टीवी कंपनियों के बीच बुनियादी ढांचा की हिस्सेदारी वितरण क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग रही है।

हिट्स दिशा निर्देश में जोड़े गये नये खंडों के मुताबिक एक हिट्स ऑपरेटर, टीवी चैनलों के वितरण के लिए लचीले तरीके से, प्लेटफार्म के बुनियादी ढ़ांचे को स्वैच्छिक आधार पर साझा कर सकता है, बशर्ते कि हिट्स प्लेटफार्म के सिगनल केवल केवल ऑपरेटर के मध्यम से ग्राहकों को वितरित किये जायें और सिगनलों का एन्क्रिप्शन, एड्रेसेबिलिटी व देनदारियों से समझौता नहीं किया जाता है। संशोधित दिशा निर्देश हिट्स ऑपरेटरों और एमएसओ के बीच हिट्स प्लेटफार्मो द्वारा प्रसारित ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम की हिस्सेदारी अनुमति देता है। इसके अलावा, हिट्स प्लेटफार्म को टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए टेलीपोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जायेगी।

एमएसओ के साथ अपनी ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम साझा करने के ईच्छुक हिट्स ऑपरेटरो को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमएसओ के पास सब्सक्राइबरों के लिए पे टीवी चैनलों के वितरण के लिए संबंधित प्रसारकों के साथ एक वैध लिखित इंटरकनेक्शत समझौता है। एक हिट्स ऑपरेटर के लिए एमएसओ के साथ बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने के लिए, ऑपरेटरों को केवल भारतीय नियंत्रित सैटेलाइटों पर साझा करने की अनुमति दी जायेगी। इस संबंध में अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) से लिखित अनुमति लेनी होगी।

जक्का जैकेब को तरक्की

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल सीएनएन-न्यूज **18** ने

promoted Zakka Jacob as managing editor. And he will lead the editorial strategy of CNN News18.

The appointment of Jacob is a good move and Zakka comes with over 18 years of experience in the industry. In his spell with CNN-News18, he has managed to carve a niche.

DTH SUBS SEES SURGE

The DTH subscription numbers have seen a surge. As per the DTH subscriber numbers by TRAI the subscribers declined from a peak of 72.44 million as on 31 March 2019 to a low of 68.92 million during the very next quarter end date – 30 June 2019

Since 30 June 2019, the number of pay DTH subscribers using services provided by private DTH service providers has been increasing slowly until 30 June 2020. As on 30 June 2020, the number of pay DTH subscriber using services provided by private DTH service providers stood at 70.58 million. This is in addition to the subscribers of DD Free Dish (free DTH services of Doordarshan).

CABLE TV ACHIEVES FULL DIGITISATION

TRAI reports state that the country has achieved 100 percent digitization of cable TV network.

As on 30 June 2020, there were 1,666 MSOs registered with the ministry of information & broadcasting (MIB) as compared to 1,613 MSO registered as on 31 December 2019. Further, as per the data reported by MSOs/HITS operators, there were 12 MSOs and one HITS operator who had a subscriber base of more than one million.

RAJAT SHARMA NEW NBA PRESIDENT

India TV editor-in-chief Rajat Sharma was re-elected as the president of the National Broadcasting Association (NBA) at its 13th annual general meeting. The board has elected News24 Broadcast India Ltd chairperson-cum-MD Anuradha Prasad as its vice president, and Bennett, Coleman & Co Ltd - Times Network MD and CEO MK Anand as honorary treasurer for the year 2020-2021.

प्रवंध संपादक के रूप में पदोन्नत किया है। श्री जैकाब की नियुक्ति एक अच्छा कदम है और जक्का को उद्योग में 18 साल से अधिक का अनुभव है।

सीएनएन–न्यूज 18 के साथ अपने कार्यकाल में वे अपना एक जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

डीटीएच सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी

डीटीएच सब्सक्राइबर सख्या में वृद्धि देखी गयी है। हालांकि ट्राई द्वारा डीटीएच ग्राहकों की संख्या के अनुसार 31 मार्च 2019 को सब्सक्राइबरो की संख्या 72.44 मिलियन के शिखर से 30 जून 2019 को बिल्कुल अंतिम तीमाही के अंतिम दिन घटकर 68.92 मिलियन रह गयी।

30 जून 2019 से निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने वाले पे डीटीएच ग्राहकों की संख्या 30 जून 2020 तक धीरे धीरे बढ़ रही थी। 30 जून 2020 तक निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का उपयोग करके पे डीटीएच ग्राहकों की संख्या 70.58 मिलियन पर पहुंच गयी। यह डीडी फ्री डिश (दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवाओं) के ग्राहकों के अतिरिक्त है।

केबल टीवी पूरी तरह डिजिटाइज हुई

ट्राई की खबरो के मुताबिक देश में केबल टीवी नेटवर्क ने 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन प्राप्त कर लिया है। 30 जून 2020 तक सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के साथ 1666 एमएसओ पंजीकृत थे इसकी तुलना में 31 दिसंबर 2019 तक 1613 एमएसओ पंजीकृत थे। इसके अलावा एमएसओ/हिट्स ऑपरेटरो द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ों के मुताबिक 12 एमएसओ और एक हिट्स ऑपरेटर ऐसा है जिनके पास एक मिलियन से अधिक का सब्सक्राइबर आधार है।

एनबीए के नये प्रधान रजत शर्मा

इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा को अपनी 13 वीं वार्षिक आम बैठक में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) को फिर से अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। बोर्ड ने न्यूज 24 ब्रॉडकास्ट इंडिया लि. की अध्यक्ष व एमडी अनुराधा प्रसाद को अपना उपाध्यक्ष और बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लि–टाइम्स नेटवर्क के एमडी वी सीईओ एमके आनंद को वर्ष 2020–21 के लिए मानद कोषाध्यक्ष चुना है।

The other members on the NBA Board are: -

- Mathrubhumi Printing & Publishing Co Ltd *MD* MV Shreyams Kumar
- TV18 Broadcast Ltd *MD* Rahul Joshi
- ABP Network Pvt Ltd *CEO* Avinash Pandey
- Eenadu Television Pvt Ltd *Director* I Venkat
- TV Today Network Ltd *Vice-Chairperson and MD* Kalli Purie Bhandal
- New Delhi Television Ltd *Editorial Director* Sonia Singh
- Zee Media Corporation Ltd *CEO - cluster 1* Sudhir Chaudhary

MSO LICENSES PENDING

Govt has yet to approve 109 MSO license applications at the end of October 2020.The Ministry in October received 4 new applications for an MSO license taking the number of MSO license applications received since April 2019 to 243 from 239 at the end of September 2020.

The Ministry in October approved 4 applications for a MSO license taking the number of MSO license applications approved since April 2019 to 134 from 130 at the end of September 2020.

The Ministry now has 109 MSO license applications pending at the end of October 2020, the same as that at the end of September 2020 which was at 73 at the end of April 2019.

HYBRID STBS TO BE LAUNCHED

GTPL Hathway will roll out Android set-top box in a phased manner across the country.

The company will also launch the Hybrid box in select Phase-III and Phase-IV markets with subsequent roll out in other markets. The hybrid box is expected to launch in Q3 FY 21 with the company indulged in pricing strategy and other things last month which will be launched at a competitive price whereby they can attract a good demand from the customer.

The company further stated that cable TV subscription was not affected by OTT with both linear TV and OTT likely to co-exist going forward. ■

एनबीए बोर्ड में अन्य सदस्य हैंः

- मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन्स कंपनी लिमिटेड के *एमडी* एमवी श्रेयम कुमार
- टीवी18 ब्रॉडकास्ट लि. *एमडी* राहुल जोशी
- एबीपी नेटवर्क प्रा.लि. *सीईओ* अविनाश पांडे
- ईनाडु टेलीविजन प्रा.लि. के *निदेशक* आई वेंकट
- टीवी टूडे नेटवर्क लि. के *उपाध्यक्ष व एमडी* कल्ली पुरी भंडाल
- न्यू दिल्ली टेलीविजन लि. की *संपादकीय निदेशक* सोनिया सिंह
- जी मीडिया कॉरपोरेशन लि. के *सीईओ–क्लस्टर1* सुधीर चौधरी

एमएसओ लाइसेंस लंबित

अक्टूबर **2020** के अंत में सरकार को **109** एमएसओ लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी देनी है। मंत्रालय को अक्टूबर में एमएसओ लाइसेंस के लिए **4** नये आवेदन प्राप्त हुए, जिसके चलते अप्रैल **2019** से प्राप्त हुए एमएसओ लाइसेंस आवेदनों की संख्या सितंबर **2020** के अंत में **239** से **243** हो गयी।

मंत्रालय ने अक्टूबर में चार एमएसओ लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी दी जिसके साथ ही अप्रैल **2019** में अनुमोदित एमएसओ लाइसेंस की संख्या **130** से बढ़कर सितंबर **2020** तक **134** हो गयी। मंत्रालय के पास अक्टूबर **2020** के अंत तक **109** एमएसओ लाइसेंस आवेदन लंबित है, बिल्कुल उतना ही जितना कि सितंबर **2020** के अंत में था, जो कि अप्रैल **2019** के अंत में **73** होना चाहिए था।

हाईब्रिड एसटीबी लॉन्च किया जायेगा

जीटीपीएल हेथवे देशभर में चरणबद्ध तरीके से एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स प्रस्तुत करेगा।

कंपनी अन्य बाजारों में इसकी प्रस्तुतिकरण के बाद चुनिंदा तीसरे चरण व चौथे चरण के बाजार में हाईब्रिड बॉक्स लॉन्च करेगा। उम्मीद है कि हाई ब्रिड बॉक्स को वित्तवर्ष **21** के क्यू**3** में लॉन्च किया जायेगा जिसके लिए कंपनी पिछले महीने मूल्य निर्धारण की रणनीति और अन्य चीजों में लिप्त है और इसे प्रतिस्पर्धी मूल्य पर लॉन्च किया जायेगा जिससे कि वे ग्राहकों की अच्छी मांग को आकर्षित कर सकते हैं।

कंपनी ने आगे कहा कि ओटीटी से केबल टीवी सब्सक्रीप्शन प्रभावित नहीं हुआ है, लिनियर टीवी व ओटीटी दोनों के एक साथ आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं। ■